E-Content

Master of Arts (History)

Darbhanga House, Patna University, Patna-800005

Semester-II

Course Code-CC-VI

Course Name: (History of Europe & Modern World 1919-2000)

Unit-IV- World War-II & Its Aftermath (Causes, Impact ~~& UNO~~)

Avinash Kumar

Assistant Professor-Department of History

Patna College, Patna-800005

6202393206 & avinashisavailable@gmail.com

1889 (चार्ली चैपलिन और जवाहर लाल नेहरू के जन्म का साल) में अप्रैल महीने की 20 तारीख़ को पैदा होने वाले हिटलर ने 1945 के अप्रैल महीने की अंतिम तिथि को अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कुछ देर पहले औपचारिक रूप से विवाहित अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ मौत को गले लगा लिया। अपने चुनावी अभियानों में कभी उसने कहा था कि ये धरती सब को ख़ैरात में मिली हुई चीज नहीं है। जो राष्ट्र और जाति सबसे शक्तिशाली और काबिल होगी, वही इस पर राज करेगा। जर्मन में अपने देश के बाहर प्रभाव-क्षेत्र के लिए उसने लेबेन्श्रम शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर समानता की बात करें तो यह भारतीय ग्रन्थों में वर्णित एक संस्कृत वाक्य-**"वीर भोग्या वसुंधरा**"- से काफी मेल खाती है। मुट्ठियाँ भींच कर और चेहरे की मांसपेशियों को सख्त कर जब वह अपने प्रदर्शनों में अपनी बात करता था तो उसकी बातों में आकर उसके विरोधियों को भी उसके दैवीय पुरुष हो जाने की गलतफहमी हो जाती थी। नौजवान युवा और युवती- चाहे वे जर्मनी के हों या उसके मुख़ालिफ ब्रिटेन के (हिटलर की एक प्रेमिका मिटफर्द नाम की ब्रिटिश युवती थी, जिसने वहाँ से भागकर हिटलर से मिलने की बहुत कोशिश की थी) लोग भी उसकी वक्तृत्व कला के मुरीद हो गए थे। अपने बचपन के दिनों में वह काफी ज़हीन छात्र था और उसकी स्मरण-शक्ति काबिल-ए-तारीफ थी। किसी भी देखे गए दृश्य को वह वर्षों बाद हू-ब-हू कागज पर उकेरने में माहिर था। उसकी दिली ख़्वाहिश थी कि वह एक चित्रकार बने। और कलाकार बहुत संजीदे होते हैं, भावुक होते हैं। सख्त मिजाज बाप से लाड़-प्यार न मिलने की वजह से वह लागातार माँ की ओर खिंचता चला गया जिसकी एक ही ख़्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़-लिख कर एक इज्जतदार आदमी बने। अपने पति एलॉयस के असमय मरने के बाद उसने घरेलू नौकरानी का भी काम किया ताकि उसके जीवन के एकमात्र सहारे की पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत न हो। इस कोशिश में वह अल्सर की मरीज भी हो गई। बाद में वह ब्रेस्ट कैंसर का भी शिकार बन गई। हिटलर ने माध्यमिक शिक्षा के बाद वियना की आर्ट्स एकेडमी में दाखिले की भरपूर कोशिश की, परंतु सिफ़ारिश न होने की वजह से वह नाकाम रहा।

एक बीमार माँ के लिए उसके बेटे की नाकामी एक अभिशाप से कम न थी| कुछ दिनों के बाद वह भी भगवान को प्यारी हो गई|

अनाथ और असहाय हिटलर को ढाढ़स बंधाने वाला कोई नहीं थे| एक यहूदी लड़की से एकतरफा प्यार में विफल हिटलर बेकार की बातों और नाउम्मीदी से घिरा हुआ था| उस वक्त के ऑस्ट्रिया में (जन्मजात हिटलर जर्मन न होकर ऑस्ट्रियन था) सामंती व्यवस्था ही थी जिसमें सामाजिक पृष्ठभूमि ही भाग्य का निर्णय किया करती थी| सामाजिक पूँजी के नाम पर हिटलर के पास कुछ भी नहीं था| ऐसे में उसने उस क्षेत्र का चुनाव किया जिसमें किसी सिफ़ारिश की जरूरत नहीं थी| बेशक यह क्षेत्र सेना के अलावे कोई हो ही नहीं सकता था| क्योंकि सामाजिक पूँजी में धनवान लोगों के लिए मौत का बहुत बड़ा होता है| लेकिन क्षीणकाय और पीनवक्षी हिटलर को वहाँ किसी सैनिक अधिकारी की जगह डाकिये का काम मिला| लेकिन प्रथम विश्व-युद्ध के अंत के दिनों में उसे फौजी भूमिका में लड़ने का अवसर मिला और जबर्दस्त प्रदर्शन के बदौलत वह वीरता पुरस्कार-आइरन क्रॉस-जीतने में कामयाब रहा| इस कामयाबी की वह ख़ुशी मनाता, इससे पहले वह क्लोरीन गैस का शिकार हो गया और अपनी आँखों का इलाज करवाने केलिए सैन्य अस्पताल में भर्ती हो गया| रोगी-शय्या पर ही उसने जर्मनी के आत्मसमर्पण की ख़बर सुनी| वह ख़ून के घूँट पीकर रह गया| उसने मैदान-ए-जंग में सैनिकों के संघर्ष को देखाठा और उसका विश्वास था कि आत्मसमर्पण जर्मन राजनेताओं ने किया था, जर्मन सैनिकों ने नहीं|

लेकिन वह कुछ ज्यादा कर पाने की हालत में नहीं था| उसने वास्तविकता को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन -पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ किए गए वर्साय की संधि की शर्तों और जिस ज़लालत में जर्मन प्रतिनिधियों को उस पर दस्तख़त करना पड़ा-दोनों ने उसके सब्र के बांध को तोड़ दिया और वह प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता रहा| प्रशियन जमींदारों और सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उसने नवगठित वाइमर सरकार के ख़िलाफ कई षड्यंत्र किए, पर बार-बार वह नाकामयाब होता रहा और अंतत: जेल में दल दिया गया| जेल में ही उसने अपनी आत्मकथा-मीन कैम्फ़-(मेरा संघर्ष) लिखी| बेहद साफदिल होकर उसने उसमें अपनी पूरी भावी योजना का खुलासा किया| सत्ता मिलने पर वह मीनकैम्फ़ में बताई अपनी योजना से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ| तानाशाह अपने उद्देश्यों को लेकर बड़े साफ होते हैं- हिटलर इसका अपवाद नहीं था| चर्चिल ने "द्वितीय विश्वयुद्ध की कहानी" नामक अपनी किताब में ये माना है कि मीनकैम्फ़ पढ़नेवाला कोई भी व्यक्ति हिटलर के अगले कदम का सहज ही पूर्वानुमान लगा सकता था|

महामंदी की शुरुआत में और वाइमर गणतन्त्र द्वारा युद्ध के हरजाने को चुकाने में असमर्थता जताने के बाद एक बार हिटलर ने राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग से अनुरोध किया था कि वे उसे चांसलर बना दें तो जर्मनी की सभी समस्याओं को वह चुटकियों में हल कर देगा| उस समय हिंडेनबर्ग ने उसका मख़ौल उड़ाते हुए कुटिलता और व्यंग्य के साथ कहा थी कि वे उसे चांसलर तो बहुत दूर की बात रही, डाकिया भी नहीं बनाएँगे| (हिटलर ने अपनी जिंदगी डाकिया के रूप में ही शुरू की थी)| पर इसे किस्मत का खेल कहा जाय या कुछ और, पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद भी उसी हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद थाली में परोसा और उसे इस पद की शपथ दिलवाई- 30 जनवरी 1933 को| **ध्यातव्य रहे इसी तिथि को पूरे 15 साल बाद गांधी जी की हत्या हुई थी और इसी साल हिटलर के शपथ से 35वीं दिन सर्वाधिक दिनों तक अमरीकी राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट ने अपने पद की**

शपथ ली थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के जो बादल प्रथम विश्वयुद्ध की भस्मावृत चिंगारी से उठ रहे थे, उसके पटाक्षेप का आगाज हो चुका था।

मोटे तौर पर द्वितीय विश्वयुद्ध एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। यह उस शृंखला की अंतिम कड़ी था जो फ्रांसीसी क्रान्ति के साथ शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रान्ति ने नेपोलियन को जन्म दिया। उसने पूरे यूरोप को रौंद डाला। फ्रांसीसी सेना जहां भी जाते-राष्ट्रवाद का संदेश-साथ में जाता। नेपोलियन ने ख़ुद कहा था कि उसने यूरोप की सोई स्वतन्त्रता की देवी को जगा दिया है। इसी राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत होकर सबसे पहले ग्रीस और उसके बाद अन्य देशों -जर्मनी और इटली- का एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण के अंतिम चरण(1870-71) में जीत के मद में चूर बिस्मार्क ने फ्रांस की वर्साय के राजमहल में भारी बेइज्जती कर दी। इसके बाद जर्मनी से बदला फ्रांस का राष्ट्रीय फर्ज बन गया। उसके कलेजे को ठंड 1919 में वर्साय में सूद सहित जर्मनी से बदला लेने के बाद मिला और जर्मन प्रतिशोध की इसी लहर पर सवार होकर हिटलर ने अपनी मंजिल हासिल की।

पर युद्ध के कारणों का इतना ज्यादा सरलीकरण सही और उचित नहीं है।

बहरहाल, द्वितीय विश्वयुद्ध के निम्नलिखित कारण थे:

1. वर्साय की आरोपित और अपमानजनक संधि:

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर नाजी पार्टी के मुख्य केंद्र न्यूरेम्बर्ग में युद्धापराध के लिए न्याधिकरण का गठन किया| नाजियों ने जिस रहा के घिनौने अपराध किए थे, उसके मुक़ाबले मात्र 11 लोगों को ही फांसी दी गई| सजा के इस बेहद निचले पैमाने को देखकर बहुत लोगों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसी तरह युद्ध शुरू करने के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी को बहुत कड़ी सजा दी गई थी|निर्णायकों का मानना था कि एक सीमा से आगे जाकर किसी पराजित देश के साथ ज़्यादती करने से प्रतिशोध की शृंखला उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि जर्मनी में हो चुका था|इससे पराजित देश को विजेता देश से बदला लेने का नैतिक आधार मिल जाता है| अब आखिर सवाल उठता है कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी के साथ क्या सलूक किया गया था?

प्रथम विश्व युद्ध के अन्त में जर्मनी और गठबन्धन देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, रूस आदि) के मध्य में हुई थी| मित्र राष्ट्रों ने सर्वप्रथम जर्मनी को **प्रथम विश्व युद्ध** का अपराधी बताकर उसके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में वर्साय संधि का मसविदा तैयार किया| मई 1919 ईसवी को संधि का मसविदा जर्मन प्रतिनिधियों को सौप दिया गया और उन्हें धमकी दी गई कि यदि वह इस मसविदे पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा| इस मसविदे पर विचार-विमर्श करने के लिए जर्मन प्रतिनिधियों को केवल दो सप्ताह का समय दिया गया| प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के पश्चात जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर किये| यह संधि 230 पृष्ठों में अंकित थी और इस संधि पत्र में 15 भाग और 440 धाराएं थी| वर्साय संधि की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी-

1- एल्सस-लॉरैन, मार्स नेट, यूक्रेन, माल्मेडी, अपर साइलेसिआ, मैमल, पोसन आदि प्रदेश जर्मनी से छीन कर फ्रांस, बेल्जियम, लिथुआनिया तथा पोलैंड को दे दिए गए| संधि की शर्तों के अनुसार एल्सस-लोरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस दे दिये गये|

2- जर्मनी के राइनलैंड का निरस्त्रीकरण कर दिया गया तथा सार घाटी पर फ्रांस का नियंत्रण स्थापित हो गया|

3- जर्मनी में सार क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था| इस प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ को सौंप दी गई, परन्तु कोयले की खानों का स्वामित्व फ्रांस को दिया गया था|

3- जर्मनी के अफ्रीका तथा एशिया स्थित सभी उपनिवेशों को मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया|

4- जर्मनी कि स्थल सेना की सीमा एक लाख निश्चित कर दी गई तथा जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया|

5- जर्मनी की नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया| अब वह 10000 टन के 6 हल्के युद्धपोत,6 हल्की क्रूजर [मालवाही जहाज] तथा 12 विध्वंसक जहाज ही रख सकता था| उनकी पनडुब्बियां भी छीन ली गई इन पनडुब्बियों को मित्र राष्ट्रों को सौंपने की बात की गई| इसके साथ ही साथ जर्मन सेना के स्टाफ को भंग कर दिया गया|

6- जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा| जर्मनी के डेजिंग बंदरगाह पर लीकऑफ नेशन का नियंत्रण स्थापित हो गया||

7- जर्मनी की नदियां तथा नील नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया|

8- जर्मनी पर युद्ध का भारी हर्जाना थोपा गया और उसे मई, 1921 ईस्वी तक 5 अरब डालर की धन राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने को कहा गया|

9- मोरक्को, मिस्त्र, बुलगारिया, चीन आदि से प्रात जर्मनी के व्यापारिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया|

10- संधि की 231वीं धारा के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्वयुद्ध के लिए के लिए उत्तरदाई ठहराया गया तथा सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को युद्ध अपराधी मानकर उस पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया|

वर्साय की संधि को इतिहास में "एक लादी गई शांति" अर्थात् "आरोपित संधि" के नाम से भी जाना जाता है| वर्साय की संधि कठोर, अपमानजनक, आरोपित, एकपक्षीय तथा अन्याय पूर्ण थी| इस संधि द्वारा जर्मनी को राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर, सैनिक दृष्टि से दुर्बल, सामाजिक दृष्टि से अपमानित तथा आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया था| वर्साय की सन्धि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, इसी कारण से इस संधि को **एडोल्फ हिटलर** और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे| यह सन्धि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थी| इस संधि से जर्मनी को छिन्न-भिन्न कर दिया गया| इस संधि ने उन लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया था जो यह कहा करते थे कि युद्ध का अंत शांति का संदेश लाएगा| यह सही अर्थों में शांति संधि नहीं थी, यह तो दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा सिद्ध हुई|

जनरल फाच ने तो संधि- पत्र के निर्माण के समय ही कह दिया था कि- **वर्साय की संधि, संधि न होकर 20 वर्षों का एक विराम काल है|** चर्चिल के अनुसार "**इस संधि की आर्थिक शर्तें इस हद तक कलंकपूर्ण तथा निर्बुद्ध थी कि उन्होंने ने इसे स्पष्टतया निरर्थक बना दिया|**"

विश्व इतिहास के जिन संधियों और उनके प्रभावों की सर्वाधिक चर्चा हुई है, उनमें वर्साय की संधि का विशिष्ट स्थान है| संक्षेप में कहा जाता है कि वर्साय की संधि मित्र राष्ट्र द्वारा बदले की भावना से जर्मनी पर थोपी गई थी| इसलिए ऐसा माना जाता है कि वर्साय की संधि में दूसरे महायुद्ध के बीज बो दिये गए थे|

लेकिन.....?

अक्सर देखा गया है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के के कारण के तौर पर इतिहास की अधिकांश किताबों में वर्साय की संधि का जिक्र मिलता है, जिसमें जर्नीन पर इसकी शर्तों के अध्यारोपण का भरपूर वर्णन होता है| लेकिन फ्रांस ने जर्मनी पर इतनी कड़ी शर्तें क्यों लादीं, इसकी पृष्ठभूमि का जिक्र न के बराबर रहता है| इतिहास कोई घटना मात्र नहीं हुआ करता, यह तो घटनाओं के एक सिलसिले के रूप में सदैव गतिमान रहा करता है|

लुई-14वां फ्रांस राजा हुआ करता था| उसके समय का कोई यूरोपियन राजा उससे मुक़ाबला नहीं कर सकता था| सब पर जीत हासिल करने के बाद वह शांति से जीवन बिताना चाहता था, लेकिन उसे हर वक्त सामंतों के विद्रोह काडसताता रहता था| इससे निजात पाने के लिए उसने अपने मंत्रियों से सलाह-मशविरा किया| सुरा और सुंदरियों की अपनी फ्रेंच परंपरा के अनुकूल ही उसके मंत्रियों ने सलाह दी कि एक ऐश-ओ-आराम से भरपूर महल बनवाये जहां सुरा और सुंदरियों की मुफ्त में उपलब्धता हो| इसी सलाह के अनुरूप उसने

राजधानी पेरिस से 20-25 किमी दूर वर्साय नामक एक जगह पर शानदार राजमहल बनाया, जहां छोटी-बड़ी हर राजसी सुख-सुविधा का बाजाब्ता इंतजाम था। राजा वहीं पर अपने सामंतों के साथ रहने लगा। इतिहास गवाह है कि इस महल के बनने के बाद किसी भी फ्रेंच सामंत ने कभी विद्रोह नहीं किया। ये तो तृतीय एस्टेट और मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने 1789 में क्रान्ति कर दी। क्रान्ति हो, चाहे नेपोलियन आए, वर्साय के राजमहल का रूतबा कभी फीका नहीं हुआ। फ्रेंच संस्कृति और राजनीति इसी के इर्द-गिर्द नाचती रही। इसमें घाटी हर घटना पर लोगों की टकटकी लगी रहती थी।

इसी राजमहल का सबसे विशिष्ट कक्ष था-शीशमहल। (भारतीय राजमहलों में इसी तर्ज पर रंगमहल का विधान है-शायद)। इस कक्ष में 1871 में बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी और पूरे फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। इतने से ही बिस्मार्क का दिल नहीं भरा, फ्रांस को जलील करने के लिए उससे अल्सेस और लोरेन का प्रांत छिन लिया। एक भारी हरजाने की राशि थोप दी गई, जिससे चुकता होने तक जर्मन सेनाएँ फ्रांस में मौजूद रखी गईं। समझौते पर हस्ताक्षर करने वक्त फ्रेंच प्रतिनिधियों के पीछे बिस्मार्क तलवार लेकर खड़ा था।

इन नज़ारों ने फ्रांसीसी राष्ट्र पर गहरा असर डाला। यह फ्रांस शुरू से यूरोपियन राष्ट्रों में सबसे ज्यादा गर्वीला और रोबीला रहा है। बेशक अंग्रेजी के लेखकों को सबसे ज्यादा साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला हो, पर ब्रिटेन से ज्यादा फ्रांस के लोगों को साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला है। यहाँ तक कि 1901 में जब पहली बार इन पुरस्कारों का ऐलान किया गया तो पहले साहित्यकार के रूप में फ्रेंच लेखक सूली प्रूधों का नाम था। अपने साम्राज्य पर ब्रिटेन का प्रभाव निर्विवाद था, पर मुख्य भूमि यूरोप में फ्रांस का बोलबाला था। उसके बनाए हर पैमाने को पूरे यूरोप में माना जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ सौ वर्षीय लड़ाई में 1431 में ही फ्रेंच लड़की जॉन ऑफ ऑर्क मशहूर हो चुकी थी। उसके क्रान्ति के आदर्श पूरे विश्व में मान्य थे। राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में-राष्ट्रमाता, राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिह्न-सब उसी के देन रहे थे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ही एकीकरण से पूर्व के जर्मन राज्यों में राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया था। उस फ्रांस के साथ बिस्मार्क ने ऐसा कुत्सित व्यवहार किया। इसने फ्रांस को न भरने वाला जख्म दे दिया।

इस के बाद फ्रांस लगातार प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा। इस राष्ट्रीय बेइज्जती को न भूलने देने के लिए वहाँ के राजनेताओं के साथ-2 साहित्यकारों, चित्रकारों और कलाकारों ने हर संभव कोशिश की। प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत के समय फ्रांस के अराष्ट्रपती रहे रेमंड पोअनकेयर ने अपनी जीवनी में लिखा था, "मेरा पूरा जीवन इस राष्ट्रीय बेइज्जती का बदला लेने में बीता।" राग-रागिनियों और सुरा-सुंदरियों के रसिया फ्रेंच कलाकारों ने भी अपनी भरपूर भूमिका अदा की। पियरे शॉनेज़ नामक फ्रेंच चित्रकार ने अपने निराश लोगों में आशा के संचार के लिए "Hope" नामक चित्र बनाया।

1870 से लेकर 1919-तकरीबन 50 सालों के इसी प्रतिशोध की स्पष्ट छाप जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि पर पड़ी।

2. राष्ट्र संघ की असफलता:

आज हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक मुद्दों का समाधान करती है| इसकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि इसने अभी तक तीसरा विश्वयुद्ध नहीं होने दिया है| ऐसा नहीं है कि इसकी स्थापना के बाद युद्ध नहीं हुए हैं, हुए तो हैं पर ये एक क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए और यूएनओ के हस्तक्षेप से उन्हें यथासंभव कम समय में रोक दिया गया है| इसके बरक्स इसका पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ ऐसा करने में सर्वथा विफल रहा था, जिसकी परिणति द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में हुई|

वर्साय संधि के कई प्रावधानों में एक प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए एक वैश्विक संस्था के रूप में राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) की स्थापना का भी था |यह कहा गया था कि "इसका उद्देश्य के तांडव से आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना है, संसार को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित स्थान बनाना है और एक ऐसी शांति की स्थापना करना है जो न्याय पर आश्रित हो|" किंतु यह मानवता का दुर्भाग्य था कि राष्ट्र संघ अपने महान आदर्शों, महत्त्वाकांक्षी सपनों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका| राष्ट्र संघ की असफलता के कारण निम्नलिखित थे-

उग्र राष्ट्रीयता – राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण विभिन्न राष्ट्रों की उग्र राष्ट्रीयता थी| प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को संप्रभु समझते हुए अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में विश्वास करते थे |कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अपने प्रभुसत्ता पर किसी का नियंत्रण स्थापित करने को तैयार नहीं था| राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धांत भले ही नये थे, किंतु उनके सदस्य राष्ट्र परंपरागत राष्ट्रीयता की संकीर्ण विचारों पर विश्वास करते थे|

सार्वभौमिकता का अभाव – विश्व शांति के लिए आवश्यक था कि विश्व के सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य होते, किंतु ऐसा नहीं हो सका| प्रारंभ में सोवियत संघ और जर्मनी को संगठन से अलग रखा गया| 1926 में जर्मनी को इसका सदस्य बना दिया गया, किंतु कुछ समय पश्चात ब्राज़ील और कोस्टारिका इससे अलग हो गए| 1933 में जापान और जर्मनी ने इसकी सदस्यता त्यागने का नोटिस दे दिया| 1934 में रूस इसका सदस्य बना| 1937 में इटली ने इसकी सदस्यता त्यागने का नोटिस दे दिया| 1939 में सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से निकाल दिया गया| इस प्रकार राष्ट्र संघ के 20 वर्ष के जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं आया, जब विश्व के सभी देश इसके सदस्य रहे हो|

अमेरिका का सदस्य न बनना – अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किंतु अमेरिका सीनेट ने सदस्यता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया| इसलिए राष्ट्र संघ को अमेरिका का सहयोग नहीं मिल सका| अमेरिका का राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के कारण संगम के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े –

- राष्ट्र संघ को अमेरिका की आर्थिक और सैनिक शक्ति से वंचित होना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई|
- अमेरिका के बाहर रहने से राष्ट्र संघ विश्व व्यापार संगठन नहीं बन सका|
  अमेरिका के सदस्य न बनने से जो राष्ट्र अपनी आशाएं और इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए वे राष्ट्र संघ से अलग होने लगे|

- अमेरिका के अभाव में फ्रांस को दी गई एंग्लो-अमरीकन गारंटी व्यर्थ हो गई और अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस ने गुटबंदियों का सहारा लिया। जिससे राष्ट्र संघ और विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा।
- राष्ट्र संघ अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन का विचार-शिशु था। लेकिन कांग्रेस ने अमरीका को इसका सदस्य बनने से मना कर दिया। राष्ट्र संघ की तरह ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना में अमरीका में सबसे अग्रणी भूमिकानिभाई। उसके सदस्य मात्र बने रहने और समुचित सहायता देते रहने से यूएनओ अब तक कामयाब है, पर अमरीकी सदस्यता और सहायता के बिना राष्ट्र संघ बेमौत मारा गया। राष्ट्र संघ की विफलता का सबसे बड़ा कारण अमरीका सदस्य न बनना था, तभी तो किसी इतिहासकार ने कहा था, ***"राष्ट्र संघ अमरीका की संतान था जिसे जन्म लेते ही उसने यूरोप के दरवाजे पर छोड़ दिया था।"***

राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध रोकने की ढीली व्यवस्था – राष्ट्र संघ के विधान द्वारा युद्ध रोकने की ढीली ढाली की व्यवस्था की गई थी। प्रसंविदा की धारा 15 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने की जो व्यवस्था थी, वह बहुत देरी करने वाली थी। विचार-विमर्श में ही काफी समय बीत जाता था और तब तक आक्रमणकारी को युद्ध की तैयारी करने का मौका मिल जाता था। धारा 16 के अंतर्गत भी कोई शक्ति पूर्ण कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती थी जब तक राष्ट्र संघ यह घोषणा न कर दे कि कोई राज्य ने संघ विधान का उल्लंघन करके युद्ध की घोषणा की है। युद्ध होने पर भी कोई राज्य अपना बचाव यह कहकर कर सकता था कि युद्ध मैंने शुरू नहीं किया है। इस प्रकार जानबूझकर की गई युद्ध को राष्ट्र संघ रोक नहीं सका।

घृणा पर आधारित – राष्ट्र संघ की स्थापना का आधार घृणा थी, क्योंकि यह संघ वर्साय संधि की ही देन थी। वर्साय संधि की प्रथम 26 धाराए राष्ट्र संघ का विधान थी। इस प्रकार यह राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग था। पराजित राष्ट्र इस संधि को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उसे अन्याय का प्रतीक मानते थे। अतः राष्ट्र संघ के प्रति उनकी दृष्टिकोण अनुदान हो गई। इस प्रकार वर्साय संधि का अंग मानकर जर्मनी ने राष्ट्र संघ को भी अस्वीकार कर दिया।

इन सब कारणों का सम्मिलित प्रभाव यह रहा कि राष्ट्र संघ अपने सबसे बड़े दायित्व युद्धों को रोकने में नाकामयाब रहा।

3. नि: शस्त्रीकरण की विफलता:

नि:शस्त्रीकरण की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि शस्त्रस्त्र सैन्य बलों को विघटित कर देने तथा आयुधों को समाप्त कर देने पर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकसित होगा, जिसमें युद्ध के स्थान पर शान्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस प्रकार **- "नि:शस्त्रीकरण उस महाविनाश को रोकने का एक प्रयास है जो युद्ध के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और जिससे सम्पूर्ण मानवता की हानि होती है।" मार्गेन्थो** ने नि:शस्त्रीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है - **"शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या उसी प्रकार के शस्त्रें की समाप्ति या कटौती नि:शस्त्रीकरण कहलाती है।"**

राष्ट्र संघ के संविधान में धारा 8 के अंतर्गत शान्ति स्थापना के लिए राष्ट्रीय शास्त्रस्त्रें को राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप कम करने के लिए नि:शस्त्रीकरण समझौतों का प्रयास करने का प्रावधान किया गया। लीग की सदस्यता ग्रहण करने वाले देशों को शस्त्र नियंत्रण को स्वीकार करने की शर्त स्वीकार करना अनिवार्य था। 28 जून 1919 की वर्साय संधि को स्वीकार करने वाले देशों ने राष्ट्र संघ के सदस्यों के रूप में अपनी सैनिक शक्ति में कमी लाने का प्रथम व्यवहारिक प्रयास किया। इसके अंतर्गत विजेता राष्ट्रों द्वारा हारे हुए देशों का अनिवार्य नि:शस्त्रीकरण किया। राष्ट्रसंघ ने अपनी नि:शस्त्रीकरण की कार्य योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए- 1। स्थायी परामर्शदाता आयोग - राष्ट्रसंघ ने नि:शस्त्रीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनवरी, 1920 में स्थायी परामर्शदाता आयोग की स्थापना की। विशुद्ध सैनिक संगठन होने के नाते यह नि:शस्त्रीकरण की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर सका। इसलिए नवम्बर, 1920 में इसमें 6 असैनिक सदस्यों को शामिल करके इसे अस्थायी मिश्रित आयोग में बदल दिया गया। अत: इससे नि:शस्त्रीकरण की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई।

जेनेवा प्रोटोकोल - इसका उद्देश्य मध्यस्थता द्वारा सुरक्षा और सुरक्षा से नि:शस्त्रीकरण के प्रयास करना था। 15 जून, 1925 को प्रोटोकोल का अनुसरण करते हुए सामान्य नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने पर विचार विमर्श हुआ लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रयास राष्ट्रसंघ द्वारा जेनेवा प्रोटोकोल व्यवस्था के तहत किया गया नि:शस्त्रीकरण का प्रयास असफल हो गया।

सज्जीकरण आयोग - 1924 में अस्थायी मिश्रित आयोग द्वारा काम करना बन्द कर देने पर इसकी जगह राष्ट्र संघ ने सज्जीकरण आयोग की स्थापना की। इसका कार्य नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए तैयारी करना था। इस आयोग ने 1930 तक नि:शस्त्रीकरण मतभेदों को दूर करने में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। 1930 में व्यापक विचार विमर्श के बाद इस आयोग ने अपनी कार्य योजना का ढांचा पेश किया। इस योजना की मुख्य बातें थी:

1. रासायनिक तथा जीवाणु फैलाने वाले युद्धों पर रोक लगाई जाए।
2. स्थल युद्ध की सामग्री का मात्रत्मक तथा गुणात्मक परिसीमन किया जाए।
3. अनिवार्य सैनिक सेवा को निश्चित सीमा तक कम किया जाए।
4. हवाई अस्त्रें को अश्व-शक्ति के आधार पर सीमित किया जाए।
5. स्थायी नि:शस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की जाए।

जेनेवा सम्मेलन - सज्जीकरण आयोग की प्रमुख बातों को ही ध्यान में रखकर 13 फरवरी, 1932 को राष्ट्र संघ का नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन जेनेवा में हुआ। इसमें 61 राष्ट्रों के 232 प्रतिनिधियों ने अपने 337 प्रस्तावों सहित भाग लिया। यद्यपि यह सम्मेलन नि:शस्त्रीकरण की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास था लेकिन मंचूरिया संकट की काली छाया भी इस पर पड़ी। इस सम्मेलन में इन बातों पर विचार हुआ।

1. आक्रमणकारी को कठोरतापूर्वक सजा देना तथा पंचनिर्णय को अनिवार्य बनाना।
2. विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करना।
3. राष्ट्र संघ की सुरक्षात्मक शक्ति का विकास अर्थात दण्डात्मक सेना का निर्माण
4. लेकिन परस्पर सहयोग की भवना के अभाव के कारण यह सम्मेलन असफल रहा।

इस सम्मेलन में प्रत्येक देश अपनी-अपनी धाक जमाने की फिराक में था। जर्मनी ने शस्त्रस्त्रें में समान कटौती का विचार रखा। उसने कहा कि वर्साय की सन्धि के अनुसार जो अन्याय उसके साथ हुआ था उसे समाप्त किया जाए। अब उसे भी अन्य यूरोपीय शक्तियों के समान ही सैन्य शक्ति का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। जब उसकी बात को मानने से इंकार कर दिया गया तो उसने राष्ट्र संघ के इस नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन से दूर होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के भेदभावपूर्ण व्यवहार व गलत नीतियों के कारण नि:शस्त्रीकरण के इस व्यवस्थित प्रयास को गहरा आघात पहुंचा।

राष्ट्र संघ के बाहर किए गए प्रयास

1919 से 1939 तक विभिन्न देशों ने विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपस में अनेक वार्ताएं की जिससे नि: शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस दौरान किए गए नि: शस्त्रीकरण के प्रयास हैं –

वाशिंगटन नौ सैनिक सम्मेलन - यह सम्मेलन 12 नवम्बर, 1921 से 6 फरवरी, 1922 तक वाशिगंटन (अमेरिका) में हुआ। इस सम्मेलन में सात सन्धियां की गई। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बैल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल, चीन व जापान के साथ भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों में नौ सेना के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय शान्ति में बाधक प्रतिस्पर्धा को रोकना था। इस सम्मेलन में 'नौसैनिक प्रतिस्पर्धा परिसीमन सन्धि पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। इस सन्धि में नवीन विशाल नौ सैनिक पोत बनाने; अड्डे स्थापित करने, वर्तमान नौ सैनिक अड्डों की नए सिरे से किला बन्दी करने पर सहमति हुई। लेकिन इस सम्मेलन में पनडुब्बियों; छोटे युद्धपोतों, विध्वंसकों के सम्बन्ध में कोई आम राय नहीं बन सकी। फ्रांस ने इस सन्धि का समर्थन नहीं किया। इसलिए इसका व्यापारिक रूप नहीं बन सका और अंतर्राष्ट्रीय नौ-सैनिक शक्तियों में निर्णय प्रतिस्पर्धा जारी रही।

जेनेवा नौ-सेना सम्मेलन - अमेरिका की पहल पर 1927 में एक नवीन नौ सैनिक समझौता करने हेतु जेनेवा में सम्मेलन बुलाया गया। फ्रांस व इटली इसमें शामिल नहीं हुए। अमेरिका, जापान व ब्रिटेन के मध्य विचार विमर्श तक ही यह सम्मेलन सिमटकर रह गया। इन तीनों देशों में भी आपस में आप सहमति नहीं बन सकी। अत: यह सम्मेलन भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

लन्दन नौ-सेना सम्मेलन - 1927 के जेनेवा सम्मेलन के असफल रहने पर नवीन प्रयास के रूप में प्रथम लन्दन नौसेना सम्मेलन 21 जनवरी 1930 को प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में नौ सैनिक शक्ति को समतुल्यता के आधार पर घटाने के लिए सभी देशों को कहा गया। इटली ने फ्रांस के साथ, जापान ने ब्रिटेन तथा अमेरिका

के साथ समतुल्यता शक्ति को घटाने पर विचार किया। इसमें हुए सन्धि के कारण अमेरिका तथा जापान ने ब्रिटेन के साथ मिलकर क्रूजरों, विध्वंसकों तथा पनडुब्बियों में भार वाहक क्षमता को सीमित करना स्वीकार किया। फ्रांस तथा इटली ने इस सन्धि पर अपनी असहमति व्यक्त की। इस सन्धि की प्रमुख बातें थीं:

1. इस सन्धि के अनुसार ब्रिटेन ने 5, अमेरिका ने 3 तथा जापान ने 1 बड़ा युद्ध पोत नष्ट करने पर सहमति जताई।
2. पांच महाशक्तियों ने 1936 तक नए युद्धपोतों के निर्माण पर रोक लगा दी।
3. सामान्य युद्ध पोतों पर 5।1 इंच से अधिक तथा बड़े युद्ध पोतों पर 6।1 इंच से अधिक व्यास की तोपें न लगाने पर सहमति हुई।
4. इसमें पनडुब्बियों का आकार 2000 टन तक घटाने पर समझौता हुआ। लेकिन इस सन्धि का एक दोष यह था कि इसकी एक धारा में हस्ताक्षर करने वाले देशों को यह अधिकार दिया गया था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खराब हो जाती है तो सन्धिकर्ता देश फिर से शस्त्रस्त्रें का निर्माण कर सकते हैं। यही प्रावधान इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था।

द्वितीय लंदन नौ-सेना सम्मेलन - इसका प्रयास 1935 में अन्तिम रूप से साकार हुआ। यह सम्मेलन 9 दिसम्बर, 1935 से आरम्भ होकर 25 मार्च 1936 तक चला। इस सम्मेलन में सभी महाशक्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर जल सेना रखने की मांग की। प्रथम सम्मेलन की तरह यह भी परस्पर विरोधी मांगों का अखाड़ा मात्र बन गया। इटली ने भी फ्रांस के साथ नौ सैनिक शक्ति की समतुल्यता की मांग की। इस तरह जापान और इटली ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। इस सन्धि पर केवल अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने ही हस्ताक्षर किए। लेकिन जापान और इटली के सहयोग के बिना यह सम्मेलन अधिक सफल नहीं रहा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने केवल भविष्य में नौ-सेना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों की सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान करने का निर्णय किया।

इस प्रकार इस दौरान किए गए सन्धियां व समझौते किसी बाध्यकारी शक्ति के अभाव के कारण असफलता का ताज बनते गए और विश्व के अनेक देशों में परस्पर वैमनस्य की भावना बढ़ती रही। सभी महाशक्तियों ने शस्त्र दौड़ को जारी रखा। अन्त में शस्त्र प्रतिस्पर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कटुता पैदा कर दी और इसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई।

इन प्रयासों की विफलता के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण सदस्य राष्ट्रों की उद्देश्य के प्रति अन्यमनस्कता रही। एकजुट होकर प्रयास करने की जगह वे सब एक-दूसरे का पैर खींचने में लगे थे। हर किसी की तिरछी निगाह दूसरे को गिराने पर टिकी थी। अपने आपको नियंत्रित करने की जगह सब दूसरे को नियंत्रित करना चाह रहे थे। ***इस स्थिति पर कटाक्ष करते हुए एक स्पेनिश समाजवादी प्रतिनिधि माद्रियागा ने एक बैठक में बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई थी: एक बार जंगल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए जानवरों ने एक सभा बुलाई। हिरणों ने कहा कि शेर के दाँत और नाखून काट देने चाहिए। शेर ने खा कि हिरणों के तेज दौड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाय। चूहों ने कहा कि साँपों के जहर निकाल देने चाहिए। छोटे जानवरों ने कहा कि हाथी और गेंडे को छोटा बना देना चाहिए।"*** अर्थात कोई अपनी ताकत को घटाना नहीं चाह रहे थे। तय था ऐसे माहौल में नि:शस्त्रीकरण के प्रयास मृग-मरीचिका ही साबित होते।

4. तुष्टीकरण की नीति:

येल इतिहासकार पाल केनेडी ने तुष्टीकरण की परिभाषा " झगड़ों को निपटाने के एक रास्ते के रूप में की है जहाँ लोगों को तार्किक बाचीत और समझौते के द्वारा शिकायतों को सन्तुष्ट कर मंहगे, खून खराबे युक्त और सम्भवत: काफी भयानक सशस्त्र संघर्ष को बचाया जाता है।''

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पेरिस में शांति-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस संधि में यूं तो विश्व के कई कई देशों के प्रतिनिधि (बीकानेर के महाराज गंगा सिंह भी)शामिल हुए थे, परंतु सब देशों का महत्त्व बराबर नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, अमरीकी राष्ट्रपति विल्सन, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लीमेंशू, इतालवाई प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, जापानी विदेशमात्री मैकिनो-ये पाँच अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। इन लोगों ने मिलकर शांति सम्मेलन को मूर्त रूप दिया। लेकिन इन सभी लोगों के उद्देश्यों में भारी विरोधाबहस मौजूद था। फ्रांस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता साता रही थी तो ब्रिटेन रूसी क्रान्ति के बाद साम्यवाद के बढ़ते खतरे से बेहद परेशान था। अमरीकी संसद प्रत्यक्षत: किसी तरह के यूरोपीय युद्ध में अपने को फँसाने के सख्त खिलाफ था। जापान की नजर अपने कमजोर पड़ोसियों पर थी। इटली उत्तरी अफ्रीका और फ्यूम पर नजर गड़ाए हुए था। फिर सामने से वे अपने आपको इकट्ठा दीखाना चाहते थे। लेकिन शांति सम्मेलन निबट जाने के बाद सब के विरोधाबहस सामने आ गए। कांग्रेस ने अमरीका को राष्ट्र संघ का सदस्य बनने की मंजूरी नहीं दी। मात्र 3 वर्षों बाद मुसोलिनी के अभ्युदय से इटली भी अपनी राह पर चला गया। जापान का लेना-देना सिर्फ चीन से रह गया था। बचे सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस-जिन पर सारा दारोमदार था इस संधि को बचाने का।

फ्रांस ने वर्साय की संधि की शर्तों को बेहद कठोर बना दिया था। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के आधार पर जर्मनी के साथ की गई ज्यादती की वह वकालत करता रहा। पर क्या ब्रिटेन भी जर्मनी के बारे में ऐसा ही ख्याल रखता था? इसका उत्तर था-बिलकुल नहीं! मुख्य भूमि यूरोप में सत्ता-संघर्ष जर्मनी और फ्रांस के बीच था। इसलिए जैसे-जैसे जर्मनी कमजोर होता जाता, वैसे-वैसे फ्रांस मजबूत होता जाता। अगर मजबूत जर्मनी प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के लिए खतरा बना था तो उसके पहले का इतिहास बताता है कि जब-जब फ्रांस मजबूत हुआ, उसने ब्रिटेन के लिए मुश्किलें खड़ी कीं। नेपोलियन ने तो ब्रिटेन की नाकेबंदी तक कर दी थी। इसलिए पराजित जर्मनी के प्रति ब्रिटेन का वैसा नजरिया नहीं था, जैसा नजरिया फ्रांस का था। साथ ही, उस समय तक विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटेन था, जो चाहता था कि जर्मनी सिर्फ नौसैनिक शक्ति का विस्तार न करे, जर्मनी की बाकी कोशिशों से उसका ज्यादा सरोकार नहीं था। वह पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार के खिलाफ जर्मनी को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल की संभावना तलाश रहा था।

सिर्फ जर्मनी ही नहीं , अन्य देशों के साथ भी इसी तरह का रवैया अपनाया। जैसे इटली और जापान के साथ।

इटली के साथ ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति

- ब्रिटेन अपने विश्वव्यापी साम्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कायम रखने के लिए भूमध्य सागर के क्षेत्र एवं सुदूर पूर्व को भी खतरों से सुरक्षित रखना चाहता था| जो इटली के सहायता के बिना अत्यंत कठिन कार्य था|
- इसलिए ब्रिटेन ने अफ्रीका में इटली के विस्तार को प्रोत्साहित किया तथा जब मूसोलीनी ने यूथोपिया पर हमला कर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो ब्रिटेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया|
- ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशन द्वारा इटली पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन नहीं होने दिया|

जापान के साथ तुष्टिकरण

- इंग्लैंड सुदूर और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए जापान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था|
- इसलिए इंग्लैंड ने मंचूरिया संकट से लेकर चीन-जापान युद्ध की घटनाओं को नजरअंदाज किया|

पेरिस शांति सम्मेलन के कुछ वर्षों बाद ही ब्रिटेन के जर्मनी के प्रति झुकाव से फ्रांस को रोष होना शुरू हो गया था| ब्रिटेन के इस बदले-बदले रूख से फ्रांस अजीब पेशोपेश में पड़ गया| उसे समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में तो वह फ्रांस के साथ रहा, युद्ध समाप्त होने पर वह जर्मनी की तरफदारी क्यों करने लगा? ***इस अजीब स्थिति को उस समय के किसी इतिहासकार ने बड़ी सटीक उपमा के साथ बताया था: ब्रिटेन और फ्रांस उस वृद्ध दंपत्ति की तरह थे, जो झगड़ते तो रहते हैं पर कभी जुदा नहीं हो सकते हैं|"*** इसी का नतीजा था कि एक दिन खुद फ्रांस ब्रिटेन की बातों में आ गया और ***तुष्टीकरण की नीति का आलम ये रहा कि म्यूनिख समझौते में खुद फ्रांस ने हिटलर की नाजायज मांगों को मान लिया|***

5. ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण:

बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण हुआ करता था| ऑस्ट्रिया का राजा हैबसबर्ग वंश का प्रतिनिधि था जिसका संबंध शार्लमान से था जो कभी पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हुआ करता था| महारानी मारिया थेरेसा और चांसलर मेटरनिख के समय पूरे यूरोप में ऑस्ट्रिया का बोल-बाला था| लेकिन प्रशा के हाथों हार (1866) के बाद उसकी स्थिति में लगातार गिरावट आती गई| प्रथम विश्वयुद्ध तो उसी के राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए शुरू किया गया था|

हिटलर ने जिस लेबेनश्रम का पालन किया, उसमें एक जर्मनभाषी राष्ट्र का वो भी जर्मनी की सीमा पर अलग रहना नानुमकिन था| जन्मजात हिटलर ऑस्ट्रियन ही था| लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन के शक्ति-संतुलन के सिद्धान्त की वजह से वह प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया को जर्मनी में नहीं मिला सकता था| इसके लिए स्थितियाँ बनाने की शुरुआत हिटलर ने चांसलर बनने के साथ शुरू कर दी थी| ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच ब्रेनर दर्रा था जहां पर इतालवी सेना तैनात थी| मुसोलिनी सिद्धांतत: उसका दोस्त था| इसलिए कोई दिक्कत होनेवाली नहीं थी| अब काम बाकी था-हिटलर के कदम उठाने पर विरोध करनेवाले ब्रिटेन और फ्रांस के रूख को जानने की| यह मौका स्पेनिश गृह-युद्ध के समय मिला जब युद्ध से भागने और डरने की फ्रांस और ब्रिटेन की कमजोरी का पता चल गया| तीसरा काम बाकी था -ऑस्ट्रिया के अंदर एक समानान्तर विरोधी खेमा तैयार करना जो सरकार के सामने ऐसी मांग रखे जिसे वो पूरा करने में असमर्थ हो| इसके लिए वहाँ नाजी दल बनाया गया, जिसका नेता इंक्वार्ट था| अपने सरकारी आवास पर हिटलर ने एक बार ऑस्ट्रियन चांसलर शुशनिग को बूलाककर इंक्वार्ट को अपने मंत्रिमंडल में रखने को बाध्य किया| शुशनिग ने ऐसा किया भी, लेकिन गत्यावरोध लगातार बढ़ते जाने से अंतत: उसने त्यागपत्र दे दिया| ऐसे में इंक्वार्ट वहाँ का चांसलर बना और उसने औपचारिक रूप से जर्मनी को ऑस्ट्रिया में अपनी सेना भेजने का निमंत्रण दिया| खून का एक कतरा बहाये हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और पूरी दुनिया यह नंगा नाच खामोश होकर देखती रही|

इस अधिग्रहण पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने संसद में चेताया था, “हमें और अन्य छोटे राष्ट्रों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि युद्ध के समय राष्ट्रसंघ हमें बचाने आयेगा|” इससे और आगे बढ़ते हुए चर्चिल ने भी चेताया था, “ वियना पर जर्मनों के प्रभुत्व के कारण नाजियों के लिए दक्षिण-पूर्व यूरोप खुल गया है| ” भावी घटनाओं से इस बात को सच साबित कर दिया| ऑस्ट्रिया पर कब्जा सिर्फ एक देश को मिलाना नहीं था, इससे हिटलर के अगले कदम को दशा और दिशा मिल गई|

6. म्यूनिख समझौता:

पेरिस शांति सम्मेलन के बाद यूरोप में कई देशों का अस्तित्व सामने आया, चेकोस्लोवाकिया उनमें से एक था| यद्यपि इसकी अधिकांश आबादी स्लाव और चेक थी, पर तीनों ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी से घिरे होने की वजह से सीमांत प्रदेशों में जर्मनभाषियों की काफी तादाद थी| अपनी विस्तारवादी योजना के तहत जब हिटलर ने लेबेन्श्रम को उछाला जिसके तहत यूरोप के सभी जर्मनभाषी क्षेत्रों को एक शासन-सूत्र में पिरोना था तो चेकोस्लोवाकिया के लिए एक असहज स्थिति पैदा हो गई| लेबेन्श्रम के तहत पहले हिटलर ने ऑस्ट्रिया को मिला लिया| इसने चेकोस्लोवाकिया को स्वाभाविक रूप से अगला निशाना बना दिया| हिटलर की उसके प्रति मंशा पहले से ही साफ थी और वहाँ अपने हस्तक्षेप की संभावना पैदा करने के लिए उसने वहाँ नाजी पार्टी का संगठन खड़ा करवा दिया| हेनलिन उसका नेता था| हिटलर की शह पर उसने चेक सरकार के आगे ऐसी मांगे रखी जिन्हें उसके लिए मानना असंभव था| इस गत्यावरोध को मुनासिब मोड देने के लिए हिटलर ने ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को अपनी तरफ मिलाया| ब्रिटेन पहले ही जर्मनी के प्रति सहानुभूति रखने लगा था| अपनी चिरशाश्वत तुष्टीकरण की नीति के अनुरूप ब्रिटेन के दबाब में फ्रांस और इटली ने म्यूनिख समझौते पर हामी भारी| म्यूनिख समझौते में जर्मनी को यह छूट दी गई थी कि वह सडेन्टेलैंड को अपने में मिला दे| सडेन्टेलैंड उस समय चेकोस्लोवाकिया के अन्दर आता था|इस समझौते पर जर्मनी, फ़्रांस, इटली और ग्रेट ब्रिटेन ने सितम्बर 29-30, 1938 को हस्ताक्षर किये थे| अतः इस समझौते में उसको भी शामिल करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ| आगे चलकर चेकोस्लोवाकिया को यह समझौता स्वीकार करना पड़ा क्योंकि इसके लिए उसके सैन्य गठजोड़ वाले मित्र देश ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दबाव डाल रहे थे|

यह अधिग्रहण 1938 के अक्टूबर 1-10 के बीच चार चरणों में किया जाना था| कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण जनमत संग्रह के बाद ही होना था|चेकोस्लोवाकिया से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी सेना और पुलिस में कार्यरत सुडेटेन जर्मनों (यदि वे ऐसा चाहें) और सभी सडेटेन जर्मन बंदियों को म्यूनिक समझौता होने के चार सप्ताह के अन्दर मुक्त कर दे| लेकिन अधीर हिटलर के लिए संयम का कोई महत्त्व नहीं था| उसकी क्षेत्रीय आकांक्षाएँ ऑस्ट्रिया को मिलाने के बाद बढ़ गई थी और वह यथाशीघ्र चेकोस्लोवाकिया को हड़पना चाहता था| म्यूनिख समझौते का आधा वर्ष भी नहीं हुआ था कि हिटलर अपने वचनों से मुकर गया और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया| यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हो गया|

स्पष्टत: म्यूनिख समझौता एक तुष्टिकरण की कार्रवाई थी जिसका लाभ एडोल्फ हिटलर ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठा लिया| इससे इस सच्चाई का पता चलता है कि किसी भी

विस्तारवादी तानाशाही को किसी तुष्टिकरण के द्वारा संभाला नहीं जा सकता है। ***बेहद सामान्य रूप में कहा जाय तो हिटलर जैसे तानाशाह की हर मांग को उसकी अंतिम मांग मानने की बात उस खुशफहमी जैसी थी जिसमें एक कुत्ते से उम्मीद की जाती है कि 10 दिनों तक लगातार भरपेट गोश्त खाने के बाद 11वें दिन वह शाकाहारी हो जाएगा।***

म्यूनिख समझौता एक ऐसी परिघटना थी जिस पर गांधी जी ने भी अपनी प्रतिकृया व्यक्त की थी। चेकोस्लोवाकिया के साथ हुए धोखे और ब्रिटेन की घृतराष्ट्रवादी नीति पर गांधी जी ने कहा था, "एक दिन की खुशी के लिए यूरोप ने अपनी शाश्वत शांति खो दी।" इतना ही नहीं समझौते के दस्तावेज़ को दिखाते हुए हीथ्रो हवाई अड्डे से उयतरने के बाद नेविल चेम्बरलेन ने कहा, ***"मैंने अपने देश के लिए शांति स्थापित कर ली है।"*** चेकोस्लोवाकिया के मानचित्र को दिखाते हुए उसने संसद में कहा था, "चारों तरह जर्मनी के जबड़े में घिरे चेकोस्लोवाकिया को बचाना नानुमकिन था। एक दूर देश जिसके लोगों से हमारा कोई लेना-देना नहीं, उसकी रक्षा के लिए युद्ध में जाना कोई सही फैसला नहीं होता।" ब्रिटेन जैसे दुनिया पर राज करनेवाले देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बचकाना बयान एकबारगी अविश्वासनीय लगता है। लेकिन या सच्चाई थी। उस समय के ब्रिटेन का राजनीतिक माहौल ही ऐसा था कि युद्ध से बचने के लिए अदा की गई हर कीमत बहुत कम लग रही थी। लेकिन बेहद दूरदर्शी राजनेता के रूप में विपक्षी चर्चिल ने संसद में कहा था, "महोदय! आपको म्यूनिख में बेइज्जती और युद्ध में चुनाव का मौका मिला था। आपने बेइज्जती का चुनाव किया है। लेकिन आप युद्ध से नहीं बच पाएंगे।" इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा सटीकता का आकलन विपक्षी नेता ने किया था। इसी चर्चिल ने बाद में हिटलर के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया था।

7. फासीवादी शक्तियों का इटली में उदय

फासीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उदय मुसोलिनी द्वारा इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह पुन: महान बनाने की भूख के साथ हुआ। फासीवाद मुख्यत: अतिराष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसका ध्यान लोगों को नियंत्रित करने के लिये सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित है। यह सैन्य आदर्शों पर आधारित है जिसमें साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन और शारीरिक दक्षता सम्मलित है।

1919 के पश्चात् इटली एवं जर्मनी में फासीवाद एवं नाजीवाद के उदय के अनेक कारणों को इंगित किया जा सकता है। जैसे- मुसोलिनी की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ एवं उसका करिश्माई व्यक्तित्व, पेरिस शांति वार्ता में दोनों देशों की माँगों का सही प्रतिनिधित्व न होना आदि। किंतु समकालीन यूरोपीय एवं इटली-जर्मनी की परिस्थितियों ने फासिस्ट शक्तियों के उदय को संभव बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:

- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इटली की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई थी। महँगाई और बेरोज़गारी की दर उच्च थी। ऐसे में मुसोलिनी के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें समस्याओं से बाहर निकलने की आशा दी।
- प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली को मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में करने के लिये अनेक वादे किये। किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ अलगावपूर्ण व्यवहार किया गया। इससे इटली स्वयं को ठगा महसूस करने लगा। फलस्वरूप फासिस्ट शक्ति को उत्प्रेरण मिला।
- इटली निवासियों के असंतोष को दूर करने तथा साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य को लेकर मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना की।
- राष्ट्र संघ की असफलता ने सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को ठेस पहुँचाई। मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में अबिसीनिया पर आक्रमण किया और राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना की।
- नि:शस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता ने फासिस्ट दल की शस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया।
- इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति ने फासिस्ट शक्ति को नाज़ी शक्ति के साथ आने का अवसर दिया।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इटली एवं जर्मनी में फासिस्ट शक्तियों के उदय के लिये समकालीन यूरोपीय परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं और इन्हीं परिस्थितियों ने फासिस्ट शक्ति के उदय को अपरिहार्य बना दिया।

8. स्पेनिश गृह युद्ध

स्पेन का गृहयुद्ध 1936 से 1939 तक चला| यह युद्ध स्पेन के रिपब्लिकनों और राष्ट्रवादियों के बीच हुआ| इसे प्रायः लोकतन्त्र तथा फासीवाद के बीच युद्ध माना जाता है किन्तु अनेक इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध वस्तुतः वामपंथी क्रांतिकारियों एवं दक्षिणपन्थी प्रतिक्रान्तिकारियों के बीच हुआ था| इस युद्ध में अन्ततः राष्ट्रवादियों की विजय हुई और उसके पश्चात फ्रैकों अगले 36 वर्षों तक (1975 में अपनी मृत्यु तक) स्पेन का शासक बना रहा|

पापुलर फ्रंट के सत्तासीन होने के साथ एवं उनकी दक्षिणपंथी एवं मध्यमार्गियों के विरूद्ध अपनायी गयी नीतियों के कारण स्पेन गृहयुद्ध के कगार पर खड़ा हो गया| दक्षिणपंथी जनलर सांजुर्जो ने हिटलर से भेंटकर सहायता का आश्वासन प्राप्त किया| 12 जुलाई, 1936 ई| को दक्षिणपंथियों ने पुलिस अधिकारी केस्टिलो की हत्या कर दी|13 जुलाई को इस घटना से उत्तेजित हो वामपंथियों ने एक दक्षिणपंथी सेनाधिकारी काल्वो सोटेलो की हत्या कर दी| इस प्रकार स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया| 17 जुलाई को मोरक्को में स्थित स्पेनी सेनाओं ने जनरल फ्रांकों के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल फूँक दिया|दक्षिणपंथी सैन्य अधिकारियों ने भी सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया| बाद में दक्षिणपंथियों का नेतृत्व भी जनरल फ्रांकों द्वारा संभाल लिया गया| इन विद्रोहियों को सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ राजतंत्रवादियों, फासिस्ट एवं चर्च का भी समर्थन प्राप्त था| इटली एवं जर्मनी से भी इन्हें मदद मिल रही थी|

गृह युद्ध के दौरान ही सितंबर, 1936 ई|में वामपंथी फ्रांसिस्को लार्गा केवेलरो ने नवीन मंत्रिमण्डल का गठन कर उसमें समाजवादियों एवं साम्यवादियों को भी सम्मिलित किया|केवेलरों ने मजदूरों एवं कृषकों का भी सहयोग प्राप्त किया, परंतु नवंबर, 1936 ई |में जनरल फ्रांकों ने सरकार को राजधानी मेड्रिड छोड़कर बैलेशिया को राजधानी बनाने को बाध्य किया| जर्मनी एवं इटली ने जनरल फ्रांकों की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी|उधर स्पेन की वामपंथी सरकार को रूस ने सहायता प्रदान की|

इसी बीच 1937 ई|में नरमदलीय समाजवादी जुआल नेगरिन ने केवेलरों के त्याग-पत्र के पश्चात् नवीन मंत्रिमण्डल बनाया और राजधानी वेलेशिया से बार्सोलोना स्थानांतरित की परंतु, फ्रांकों की सेनाओं ने 25 जनवरी, 1939 ई| को बोर्सोलोना पर अधिकार कर लिया| 28 मार्च, 1939 ई| को फ्रांकों ने मेड्रिड में प्रवेश किया|इस प्रकार स्पेन में गृहयद्ध समाप्त हुआ और जनरल फ्रांकों स्पेन का तानाशाह बन गया|

स्पेन के गृह युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का निर्माण किया|स्पेन में गणतंत्र के विरोध ने इटली एवं जर्मनी की मित्रता को मजबूत किया|दूसरी ओर इंग्लैण्ड एवं फ्रांस से रूस नाराज हो गया|यह युद्ध गणतंत्र की पराजय एवं तानाशाही की जीत के रूप में देखा जा सकता है|वस्तुतः इंग्लैण्ड, फ्रांस एवं अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए, तानाशाही के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनायी|इंग्लैण्ड एवं फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति ने हिटलर एवं मुसोलिनी को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की और विश्व के राजनीतिक पटल पर इटली, जर्मनी, एवं जापान के साथ-साथ स्पेन के फ्रांको जैसे तानाशाह का भी उदय हुआ|

स्पेन के गृहयुद्ध के समय जो गुट बना, कमोबेश वही गुटबंदी द्वितीय विश्वववयुद्ध के दरम्यान भी बनी रही| रूस ने स्पेन की लोकतान्त्रिक और समाजवादी सरकार को सहायता दी थी जबकि लोकतन्त्र का राग आलापाने वाले ब्रिटेन ने सदैव रूस के प्रति एक संदेहास्पद नजरिया रखा|यह आगे भी बदतूर जारी रहा|इसी महत्त्व के चलते बहुत बार स्पेनिश गृह युद्ध को **"द्वितीय विश्वयुद्ध का पूर्वाभिनय"** भी कहा जाता है|

09. इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी:

महामंदी एक बड़ा आर्थिक संकट था जो 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ और 1939 तक दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ा। 24 अक्टूबर 1929 के दिन को 'ब्लैक थर्सडे' कहा जाता है। इसी तारीख़ को महामंदी के शुरू होने का दिन बताया जाता है। इस दिन न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें 25 फीसदी तक गिर गई थी। वहीं औद्योगिक उत्पादन में 47 प्रतिशत, थोक मूल्य सूचकांक 33 प्रतिशत और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत तक गिरावट आ गई थी।

महामंदी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था। 1929 से 1933 के बीच अमेरिका में बेरोजगारी 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 24.9 प्रतिशत हो गई। ब्रिटेन में यह 1929 और 1932 के बीच 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गई। महामंदी के चलते दुनिया भर में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी। यूरोप में महामंदी को फासीवाद के उदय के पीछे का प्रमुख कारण माना जाता है। जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ा।

1921 से अमेरिका की इकोनॉमी बूम पर थी। फोर व्हीलर गाड़िया, रेफ्रीजिरेटर, वॉशिंग मशीन और रेडियो जैसी चीजों का मास प्रोडक्शन होने लगा था और इसकी सेल भी काफी अच्छे से हो रही थी। नए होने के चलते इन सभी चीजों की डिमांड भी काफी ज्यादा थी। इसी के चलते सभी के बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और स्टॉक प्राइज भी तेजी से ऊपर जा रहे थे। इसी वजह से 1920 से लेकर 1928 के समय को रोरिंग ट्वेंटीज भी कहा जाता है।

1929 से अमेरिका की इकोनॉमी में स्लोडाउन आने लगा। कंपनियों की ग्रोथ धीमी होने लगी। जिन उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ी थी वो कम होने लगी। इस वजह से कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम करने लगी और कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। डिमांड और प्रोडक्शन में आई कमी की वजह से इन कंपनियों के स्टॉक प्राइज भी तेजी से कम हुए। यूस स्टील जैसी कंपनी का शेयर लगभग 250 डॉलर से गिरकर 25 डॉलर पर आ गया।

महामंदी की शुरुआत में लोगों की लगा कि ये नॉर्मल स्लोडाउन है और जल्द रिकवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे-धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगी जिसकी वजह से लोगों की ख़र्च करने की क्षमता कम होने लगी। स्टॉक मार्केट में आई गिरावट के चलते लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। जिन लोगों ने अपनी जॉब खो दी वह अपनी सेविंग को निकालने के लिए एक साथ बैंक पहुंचने लगे। लेकिन बैंकों ने काफी सारा पैसा कंपनियों को लोन के तौर पर दे रखा था। स्लोडाउन की वजह से ये कंपनियां बैंक को समय पर पैसा नहीं लौटा पा रही थी। ऐसे में कई सारे बैंकों ने डिपोजिटरों को उनका पैसा देने से मना कर दिया। इस वजह से करीब काफी सारे बैंक फेल हो गए।

बैंकों के फेल होने से लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया। इस वजह से ज्यादातर लोग अपने पास कैश रखने लगे और इकोनॉमी में पैसा आना बंद हो गया। ऐसे में कंपनियों को भी फंड रेज करने में परेशानी आने लगी। इंडस्ट्रियल आउटपुट निचले स्तर पर आ गई। देखते ही देखते लोग जिसे नॉर्मल स्लोडाउन समझ रहे थे वो मंदी में बदल गया और फिर ये महामंदी में बदल गया। सरकार महामंदी से उबरने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही थी।

इसके बाद 1933 में फ्रैंकलिन डेलानो रोज़वेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने| उन्होंने सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को सुधारने का फैसला लिया| इसके लिए उन्होंने फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) की शुरुआत की| इसके जरिए उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि बैंक में रखे पैसों की गारंटी FDIC लेगी| बैंक फेल होने की स्थिति में डिपोजिटर को उनका पैसा FDIC देगी| इसकी वजह से लोगों का भरोसा फिर से बैंकों पर बनने लगा और लोग बैंकों में पैसा डिपोजिट करने लगे|

1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया| इसका फायदा अमेरिका को मिला और इकोनॉमी ट्रेक पर आने लगी| अमेरिकी सरकार ने काफी सारा पैसा मिलिट्री में निवेश करना शुरू किया| इससे काफी सारी कंपनियों को ऑर्डर मिलने लगे और रोजगार बढ़ने लगा| इसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रेक पर आ गई|

अमरीका में इस मंदी का वैश्विक असर हुआ क्योंकि उस समय अमरीका की अर्थवयवस्था दुनिया का आधा उत्पादन कर रही थी| दुनिया भर में वाणिज्यिक उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता था| इसके प्रभाव से छोटे-बड़े सभी देश प्रभावित हुए| कुच्छ देश कम हुए तो कुच्छ जायादा| मसलन -सोवियत रूस ने समाजवादी आर्थिक नियोजन की पंचवर्षीय प्रणाली अपनाई थी, जिसकी वजह से उत्पादन पर सरकार का पूरा नियंत्रण था| इसलिए उसके यहाँ अति-उत्पादन की समस्या नहीं आई| जबकि सबसे खराब हालत जर्मनी की हुई| जर्मन करेंसी मार्क के अवमूल्यन का आलम यह था कि लोग बैग में मार्क ले जाते थे और बदले में सामान जेब में भरकर लाते थे| सैनिक छंटनी, रूर और राइनलैंड के निकलजाने और आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई थी| इस असहायावस्था में लोगों के मन में निराशा घर कर गई|

महामंदी हिटलर के उदय के लिए सबसे उपयुक्त थी| लोकतान्त्रिक सरकार कुछ कर पाने की हालत में नहीं थी| ऐसे में लोगों को आसमानी ख्वाब दिखाने में हिटलर सबसे आगे रहा| उसने लोगों से वर्साय के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की, उसने लोकतान्त्रिक सरकारों को असहाय बताया, उसने जर्मनी के सैन्यीकरण करके नौकरियाँ बढ़ाने का वादा किया, उसने मजदूर यूनियनों को नियंत्रित करके तेज औद्योगीकरण का वादा किया| एक शिक्षित और सामान्य जर्मन उसके खयाली पुलाव के चक्कर में कभी नहीं आया| लेकिन जब वह बेकार हो गया, उसकी बैंक जमा खत्म हो गई, वह सड़क पर आ गया-तो क्या अच्छा और क्या बुरा-ये सब सोचने का समय ही नहीं रहा| उसे हिटलर में एक मसीहा नजर आया जो उसके सभी समयाओं का समाधान कर देता| जैसे-जैसे मंडी गहराती चली गई, हिटलर की लोकप्रियता भी वैसे-वैसे बढ़ती चली गई| महामंदी की शुरुआत से पहले 1928 में जब चुनाव हुए तो उसे मात्र 2.5% वोट मिले, जबकि मंदी के चरम पर 1932 के चुनाव में उसे अप्रत्याशित रूप से 33% के करीब वोट मिले| 4 सालों मेन उसकी लोकप्रियता 13 गुणी बढ़ गई| साफ है, मंदी उसके विकास की सीढ़ी साबित हुई|

पर यहाँ, एक तथ्य ध्यातव्य है| तथ्य यह है कि जहां हिटलर ने मंदी का फायदा उठाकर चांसलर का पद हथियाया और उससे आगे पूरे देश को विनाश के महागर्त में धकेल देने को आतुर हुआ| उसके विपरीत उसी वर्ष राष्ट्रपति बने रूजवेल्ट ने अमरीका को बुलंदी पर पहुंचा दिया| रूजवेल्ट ने कभी सरकारों की जिम्मेदारियाँ बताते हुए कहा था, "सरकार की सिर्फ दो जिम्मेदारियाँ है-भय और भूख से अपने लोगों को बचाना|" हिटलर ने भी अपने लोगों से यही वादे किए थे, पर युद्ध को अपरिहार्य बना दिया| जबकि दूसरी ओर रूजवेल्ट ने दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया| इसलिए हर हाल में मंदी तानाशाही को जन्म देती है-शत-प्रतिशत सही नहीं कहा जा सकता|

10. हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण (तात्कालिक कारण)- सितंबर,1939

पेरिस शांति सम्मेलन में जब पोलैंड को एक देश के रूप में मान्यता दी गई तो समुद्र तक उसकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए एक बन्दरगाह का होना जरूरी था| यह निकटतम बन्दरगाह शहर था-डेंजिंग जो बाल्टिक सागर तट पर अवस्थित था| डेंजिंग जाने के लिए एक पोलिश गलियारा बनाया गया, जिसके चलते जर्मनी दो हिस्से में बाँट गया| पूर्वी प्रशा का हिस्सा इस गलियारे के दूसरी तरफ था|यह व्यवस्था 1919 से ही जर्मनी को खटकती रहती थी| लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी|हिटलर के मार्ग में यह बहुत बड़ी बाधा थी| ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के अधिग्रहण के बाद धीरे-धीरे ब्रिटेन में हिटलर को लेकर संशय लगातार बढ़ने लगा था| तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जनमत उभरने लगा था|इसका हिटलर ने सही आकलन नहीं किया|ऐसे में उसने पोलैंड के सामने न मानी जाने लायक शर्तें रखीं-डेंजिंग उसे वापस किया जाय और पूर्वी प्रशा जाने का रास्ता दिया जाय| वास्तव में यह हिटलर की चाल थी युद्ध के लिए बहाना ढूँढने की| युद्ध शुरू हो, इसके पहले पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए उसने पोलैंड के दूसरी तरफ के देश सोवियत रूस के साथ 23-24 अगस्त को अनाक्रमण संधि कर ली| पूरी व्यूह-रचना के बाद उसने इंग्लैंड को उलझाए रखने के लिए उसके राजदूत एंडरसन को अपने पास बुलाया|पोलैंड पर बहुत पहले ही विद्युत प्रहार की तैयारी की जा चुकी थी| एंडरसन ने अंत समय तक स्थिति को संभालने की बहुत कोशिश की|खुद पोप ने शांति की अपील की|परंतु इन सब का सनकी हिटलर पर कोई असर नहीं पड़ा|उसका आकलन था कि पोलैंड का नाश इतनी जल्दी कर दिया जाएगा कि ब्रिटेन को उसकी सहायता देने तक का अवसर नहीं मिलेगा और जिस तरह ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण सिर्फ धौंस दिखाकर हो गया था, पोलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा|पहली सितंबर 1939 को एकदम सुबह साढ़े पाँच बजे ही जर्मन फौज ने सीमा चकियों को तबाह करते हुए पोलैंड में प्रवेश कर लिया| ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को कड़े संदेश भेजकर अपनी सेना बुलाने काओ कहा, पर वह टस-से-मस नहीं हुआ| अंतत: 3 सितंबर को चेम्बरलेन ने सवा ग्यारह बजे जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी| इसके 6 घंटे बाद फ्रांस ने भी ऐसा ही किया|आयरलैंड को छोड़कर पूरे साम्राज्य ने भी ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी|ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भी ऐसा किया| कांग्रेस से सलाह-मशविरा किए बिना वायसराय द्वारा ऐसी घोषणा के विरोध में केंद्रेयाय मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया| द्वितीय विश्वयुद्ध की औपचारिक शुरुआत हो चुकी थी जो तकरीबन एक माह कम 6 वर्षों के बाद खत्म हुआ|

द्वितीय विश्वयुद्ध का उत्तरदायित्व

- यह विवादास्पद है की द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदाई कौन था| सामान्यता **वर्साय की अपमानजनक संधि**, **राष्ट्र संघ की विफलता ,विश्व आर्थिक मंदी** जैसे कारणों को द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदाई माना जाता है|
- वास्तविकता यह है कि 1938 तक वर्साय की संधि के अनेक आपत्तिजनक प्रावधानों को समाप्त किया जा चुका था, तथा जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रुप में उभर चुका था|
- अनेक इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर पोलैंड पर अधिकार कर प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाहता था|साथ ही पोलैंड और सोवियत संघ पर अधिकार कर वह **साम्यवाद के प्रसार** को रोकना चाहता था| इसलिए हिटलर की नीतियां ही मुख्य रूप से द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी बनी|
- अनेक विद्वान इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति को द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदाई मानते हैं| म्यूनिख समझौता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चेंबरलेन द्वारा चेकोस्लोवाकिया की सहायता नहीं किए जाने से भी हिटलर को सुडेटनलैंड पर अधिकार करने का अवसर मिल गया|
- कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि सोवियत संघ और जर्मनी की संधि भी युद्ध के लिए उत्तरदाई थी| सोवियत संघ को जर्मनी के साथ संधि करने की जगह पोलैंड और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संधि करनी चाहिए थी| इस से भयभीत होकर हिटलर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं करता|
- इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए हिटलर के अतिरिक्त इंग्लैंड फ्रांस और सोवियत संघ भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई थे फिर भी अधिकांश इतिहासकार हिटलर और उसके नाजीवाद को द्वितीय विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदाई मानते हैं|

द्वितीय विश्वयुद्ध की प्रमुख घटनाएं

युद्ध का आरंभ

1 सितंबर 1939 को को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध का बिगुल बज उठा| शीघ्र ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी| उधर जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया| 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक का काल न**कली युद्ध अथवा फोनी वार** का काल माना जाता है क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति बने रहने पर भी कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ| 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया| जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलेंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया| बाध्य होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा| फ्रांस के बाद इंग्लैंड की बारी आई| जर्मन बमवर्षकों ने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई|परंतु इंग्लैंड की लड़ाई में जर्मनी को सफलता नहीं मिली|वह इंग्लैंड पर अपना अधिपत्य नहीं जमा सका|जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया परंतु सोवियत संघ ने मास्को की ओर जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोक कर उसे वापस लौटने को विवश कर दिया|

युद्ध का विस्तार

1941 से यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया भी युद्ध की लपेट में आ गया| 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर दिया|फलतः अमेरिका भी युद्ध में सम्मिलित हो गया| जापान ने शीघ्र ही मलाया, वर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि पर अधिकार कर लिया| भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा मंडराने लगा| इस प्रकार युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा अन्य मित्र राष्ट्र एक पक्ष में तथा दूसरे पक्ष में जर्मनी, इटली, और जापान आ गए| अब युद्ध का प्रसार तेजी से हुआ| मास्को की ओर बढ़ने से रोकने पर जर्मनी ने सोवियत संघ के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया| सितंबर 1942 में जर्मन सेनाएं स्तालिनग्राद तक पहुंच गई|परन्तु स्तालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई| यहां से जर्मनी की पराजय की प्रक्रिया आरंभ हो गई| सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया जो जर्मनी के नियंत्रण में थे पर अपना आधिपत्य जमा लिया| सोवियत संघ ने जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा फ्रांस के नारमंडी में खोल दिया|इससे जर्मन सेना को दो मोर्चो पर लड़ना पड़ा|फलतः उसकी शक्ति कमजोर पड़ती गई|अमेरिका के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भी धुरी राष्ट्रों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी|

युद्ध का अंत

1944 में पराजित होकर इटली ने आत्म समर्पण कर दिया| इससे जर्मन शक्ति को आघात लगा|स्तालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी को परास्त कर सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए बर्लिन जर्मनी तक पहुंच गई|बाध्य होकर 7 मई 1945 को हिटलर को आत्मसमर्पण करना पड़ा|6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा कर उन्हें पूर्णता नष्ट कर दिया|लाखों की संख्या में निर्दोष व्यक्ति मारे गए बाध्य होकर जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा|इस प्रकार विनाशकारी द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया|

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम प्रथम विश्वयुद्ध से अधिक निर्णायक हुए। इसके सिर्फ विनाशकारी प्रभाव ही नहीं हुई, बल्कि कुछ प्रभाव ऐसी भी है जिससे विश्व इतिहास की धारा बदल गई तथा एक नए विश्व का उदय और विकास हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए:

धन-जन का भीषण संहार

द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रथम विश्वयुद्ध की तुलना में धन-जन की अधिक क्षति हुई। एक अनुमान के अनुसार, इस युद्ध में दोनों पक्षों के 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए जिनमें सर्वाधिक संख्या सोवियतों की थी। लाखों बेघर हो गए। इससे पुनर्वास की समस्या उठ खड़ी हुई। लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। घायलों की गिनती ही नहीं की जा सकती थी। परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह नष्ट हो गए। इसी प्रकार युद्ध में बेहिसाब संपत्ति भी नष्ट हुई। अनुमान था सिर्फ इंग्लैंड में करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई। सोवियत संघ की संपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति का चौथा भाग युद्ध की भेंट चढ़ गया। इतना विनाशकारी युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था।

औपनिवेशिक युग का अंत

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सभी साम्राज्यवादी राज्यों को एक-एक कर अपनी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। उपनिवेशों में राष्ट्रीयता की लहर तेज हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गए। फलतः एशिया के अनेक देश यूरोपीय दासता से मुक्त हो गए। यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति और साधन इतने कमजोर हो गए कि वह उपनिवेशों पर अपना कब्जा जमाए रखने में सक्षम नहीं र।हे इसलिए वर्मा, मलाया इत्यादि स्वतंत्र हो गए। 1947 में भारत भी अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गया।

फासीवादी शक्तियों का सफाया

युद्ध में पराजित होने के बाद धुरी राष्ट्रों के दुर्दिन आ गए। जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उससे छिन गया। इटली को भी अपने सभी अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर वह अपना अधिकार जमाए हुए था। इन राष्ट्रों की आर्थिक सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई।

इंग्लैंड की स्थिति का कमजोर पड़ना

अब तक विश्व राजनीति में इंग्लैंड ब्रिटेन की प्रमुख भूमिका थी। वह एक शक्तिशाली राष्ट्र था। परंतु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उसकी स्थिति दुर्बल हो गई।भारत सहित उसके सभी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तथा विश्व राजनीति में उस का दबदबा घट गया।

सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस के स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव विश्व राजनीति में बढ़ गया। इन्हीं दोनों देशों के इर्द-गिर्द युद्धोत्तर राजनीतिक घूमने लगी।

साम्यवाद का तेजी से प्रसार

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों एशियाई देशों चीन। उत्तर कोरिया इत्यादि देशों में साम्यवाद का प्रसार हुआ। साम्यवाद के प्रसार से फासीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों की कमर टूट गई। वह पुनः सिर उठाने लायक नहीं रहे।

विश्व का दो खेमो में विभाजन और शीत युद्ध

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के 2 महान शक्तिशाली देश बन गए। अमेरिका पूंजीवाद और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। यद्यपि सोवियत संघ को युद्ध में अपार क्षति हुई थी तथापि उसने शीघ्र ही अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली। अमेरिका की स्थिति पहले से ही मजबूत थी। अतः यूरोपिय और एशियाई

देश सहायता के लिए सोवियत संघ एवं अमेरिका की ओर आकृष्ट हुए| दोनों ने और विकसित और विकासशील देशों को अपने प्रभाव में लेना आरंभ कर दिया| फलतः विश्व के राष्ट्र दो खेमों में बंट गए| पूर्वी यूरोप चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव में आए| इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और एशिया के कुछ राष्ट्र पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक बनकर अमेरिका के प्रभाव में चले गए| सोवियत संघ और अमेरिका दोनो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में लग गए| इससे शीत युद्ध आरंभ हुआ इसकी समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के बाद ही हुई|

गुटनिरपेक्षता की नीति

इन दो खेमों में जाने की अपेक्षा कुछ एशियाई ,अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया| इसी प्रकार विश्व राजनीति में एक तीसरी शक्ति के रूप में असंलग्न राष्ट्रों का उदय हुआ| गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तेजी से प्रसार हुआ| इस आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है|

जर्मनी का विघटन

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी को दो भागों में विभक्त कर दिया गया| पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी| पश्चिमी जर्मनी को इंग्लैंड अमेरिका और फ्रांस तथा पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ के संरक्षण में रखा गया| बर्लिन की दीवार बनाकर इसका विभाजन किया गया| विगत वर्षों में जर्मनी का पुनः एकीकरण कर बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई है तथा जर्मनी पर से विदेशी आधिपत्य समाप्त कर दिया गया है|

वैज्ञानिक प्रगति

द्वितीय विश्वयुद्ध में वैज्ञानिक खोजों में प्रगति हुई| कुछ वैज्ञानिक आविष्कार तो मानव सभ्यता के लिए लाभदायक थे, परंतु कुछ के घातक परिणाम भी हुए |प्राकृतिक रबर के स्थान पर कृत्रिम रबर का विकास किया गया| संक्रामक बीमारियों से रक्षा के नए उपाय खोजे गए| अमेरिका में पेनिसिलिन का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ|रक्त के प्लाज्मा निकालने की विधि खोजी गई जिससे घाव से होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी आई| इसी प्रकार युद्ध के लिए बमवर्षक विमानों, जेट इंजन एवं रॉकेट का निर्माण किया गया| रेडार का भी विकास किया गया| सबसे महत्वपूर्ण था परमाणु बम का निर्माण, जिसका उपयोग अमेरिका ने जापान के विरुद्ध किया| युद्ध की समाप्ति के बाद परमाण्विक हथियारों के निर्माण की दौड़ विश्व में आरंभ हो गई है| इससे विश्व युद्ध का खतरा पुनः बज गया है|

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पुनः प्रतीत हुई, जिससे कि विश्व शांति बनाए रखी जा सके एवं विश्व युद्ध की पुनरावृति को रोका जा सके| अमेरिका के पहल पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र नामक संघ की स्थापना हुई| यस सही है कि राष्ट्र संघ की कब्र पर इसका गठन हुआ, परंतु राष्ट्र संघ की गलतियों से इसे पूरी तरह बचाया गाया| अमरीका समेत विश्व के प्रमुख पाँच देश-सोवियत रूस, फ्रांस , ब्रिटेन और चीन-इसके संरक्षक बने और उन्हें वीटो का अधिकार दिया गया| इसकी सैन्य शक्ति और वितते शक्ति बहुत ज्यादा थी| इसके राजस्व की भी बेहतर व्यवस्था थी| इसने उन मुद्दों के समाधान के बेहतर प्रयास किए जिनके परिणामस्वरूप युद्ध जन्म लेते हैं| इसने कई देशों को आजादी हासिल करने में सहायता की है| वैश्विक भूख, महामारी और निरक्षरता को समाप्त करने में इसकी सराहनीय भूमिका रही है| अंत:-सांस्कृतिक सम्बन्धों को इसने मजबूत किया है| अभी तक तृतीय विश्वयुद्ध की कोई संभावना नहीं दीख रही, यही इसकी सफलता कही जाएगी|